eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

अमेरिका–ईरान संघर्ष एवं Strait of Hormuz संकट के संदर्भ में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता

मुकेश कुमार पाण्डेय[1], प्रो0 ए0 पी0 सिंह[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, एस0 एम0 कॉलेज, चंदौसी उ0प्र0
[2]शोध निर्देशक, राजनीति शास्त्र विभाग, एस. एम. कॉलेज, चंदौसी (सम्बद्ध: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली)

Received: 21 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 31 March 2026

Abstract

2026 के पश्चिम एशिया संकट, विशेष रूप से ईरान–इजराइल–संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न अस्थिरता ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को गहराई से प्रभावित किया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक आयात–निर्भर है, इस संकट के बीच एक बहुआयामी रणनीति अपनाता हुआ दिखाई देता है। इसमें आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, वैकल्पिक समुद्री मार्गों का उपयोग, रणनीतिक भंडारण क्षमता का विस्तार तथा घरेलू उत्पादन वृद्धि शामिल है। साथ ही, भारत की समुद्री रणनीति—हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और बहुपक्षीय सहयोग—ऊर्जा सुरक्षा को व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। यद्यपि भारत ने अल्पकालिक संकट प्रबंधन में सफलता प्राप्त की है, फिर भी हॉर्मुज पर आंशिक निर्भरता एक संरचनात्मक जोखिम बनी हुई है। कूटनीतिक स्तर पर, सीमित प्रभाव–क्षमता के कारण भारत की मध्यस्थता भूमिका भी यथार्थवादी सीमाओं से बंधी है। अतः, दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता भारत की प्राथमिक आवश्यकता बनी हुई है।

मुख्य शब्द – हिंद–प्रशांत, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति विविधीकरण, समुद्री रणनीति, रणनीतिक स्वायत्तता

Introduction

मध्य–पूर्व की भू–राजनीति के विशाल रंगमंच पर, जहाँ विश्वास और शक्ति की प्राचीन दरारें आधुनिक ऊर्जा प्रवाह की अथक धाराओं से टकराती हैं, ''होर्मुज जलडमरूमध्य'' विश्व अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा के उस संकीर्ण गले के रूप में उभरता है, जिससे गुजरना अनिवार्य है। ईरानी पठार और अरबी प्रायद्वीप के बीच स्थित इन नीले जलों में एक गहन संरचनात्मक असंतुलन स्पष्ट दिखाई देता है — लगभग नौ करोड़ जनसंख्या वाला एक क्रांतिकारी अग्नि में तपाया हुआ राष्ट्र, छह खाड़ी राजतंत्रों के समूह के सामने खड़ा है, जिनकी कुल नागरिक आबादी सत्ताईस मिलियन से भी कम है। यह आंकड़ा मात्र जनसांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता की छिपी हुई वास्तुकला है — एक ऐसा संघर्ष जो कूटनीति, छद्म युद्ध और महाशक्तियों के संरक्षण की सीमाओं को बार–बार परखता रहा है।

परंतु इस प्रतिद्वंद्विता का सबसे भयावह रूप उसी जलडमरूमध्य में प्रकट होता है, जो मात्र तैंतीस किलोमीटर की अपनी सबसे संकरी चौड़ाई पर भी विश्व के सबसे बड़े सुपरटैंकरों को वहन करने में सक्षम है। यहीं प्रतिदिन लगभग दो करोड़ बैरल तेल और वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का पाँचवाँ भाग परिवहन होता है। यह कोई साधारण समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि हिंद–प्रशांत व्यवस्था के संतुलन का निर्णायक केंद्रीय बिंदु है, जिस पर भारत की उन्नति अत्यंत निर्भर है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

इतिहास ने क्रूर निरंतरता के साथ सिद्ध किया है कि यह चोकपॉइंट कितना नाजुक है। 1980 के दशक के 'टैंकर युद्ध' में वही जल, जो कभी दारा और सासानी व्यापार का साक्षी थे, जलते हुए जहाजों का कब्रिस्तान बन गए थे। आज उसी संघर्ष की गूँज जून 2025 तथा 2026 की घटनाओं में सुनाई देती है — जब ईरानी संसद द्वारा जलडमरूमध्य को बंद करने की मंजूरी, अमेरिकी हमलों और ईरान की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीमा लागत आसमान छू गई, नौसैनिक यातायात में 95% की कमी आई, तेल की कीमतें सौ डॉलर प्रति बैरल के निकट पहुँच गईं तथा एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक मुद्रास्फीति, ईंधन राशनिंग तथा बिजली कटौती की लहरें दौड़ गईं।

भारत के लिए यह कोई दूर की खबर नहीं थी। अपना लगभग साठ प्रतिशत कच्चा तेल इसी मार्ग से आयात करने वाला और खाड़ी क्षेत्र में लगभग आठ लाख प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाला भारत इस संकट को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच के अटूट संबंध का जीवंत उदाहरण मानता है। इस प्रकार, होर्मुज जलडमरूमध्य मात्र एक समुद्री गलियारा नहीं, बल्कि हिंद–प्रशांत के भविष्य का वह निर्णायक धुरी है, जिस पर भारत का दृष्टिकोण अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। थ्यूसीडीडीज के युग से लेकर कल के शीर्षकों तक की इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि जब महत्त्वपूर्ण चोकपॉइंट्स काँपने लगते हैं, तब उभरती हुई शक्तियाँ दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं। उन्हें सूक्ष्म, बहुस्तरीय रणनीति बुननी पड़ती है — रूस, अफ्रीका और अमेरिका से आपूर्ति विविधीकरण, दुक्म से चाबहार तक नौसैनिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना तथा विश्व मंच पर संप्रभुता और मुक्त नौवहन के सिद्धांतों के लिए एक सशक्त एवं नैतिक स्वर उठाना। केवल इसी संतुलित राजनयिकता के माध्यम से भारत अपनी दुर्बलता को अवसर में परिवर्तित कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि होर्मुज के संकीर्ण जल उसकी नियति की सीमा न बन जाएँ।

ईरान–खाड़ी संबंधों का ऐतिहासिक विकास:

मध्य–पूर्व में ईरान और अरब खाड़ी देशों के बीच वर्तमान प्रतिद्वंद्विता को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण आवश्यक है। औपनिवेशिक काल में लगभग डेढ़ शताब्दी तक ब्रिटेन ने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संरचना स्थापित कर रखी थी, जिसमें उसने छोटे अरब राजतंत्रों की रक्षा करते हुए ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। यह "ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था" क्षेत्रीय स्थिरता का आधार थी। किन्तु 1971 में खाड़ी देशों की स्वतंत्रता के साथ ही यह संरचना समाप्त हो गई और शक्ति संतुलन का नया दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें ईरान ने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई।

इस परिवर्तन को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाली घटना Iranian Revolution थी, जिसने ईरान की राजनीतिक और वैचारिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया। क्रांति के पश्चात ईरान ने पारंपरिक राष्ट्रवाद के स्थान पर शिया क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया और अपने प्रभाव का विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया, जिससे सुन्नी अरब देशों के साथ वैचारिक एवं सामरिक तनाव बढ़ गया। इसके बाद Iran–Iraq War (1980–88) ने इस प्रतिद्वंद्विता को और तीव्र कर दिया, जिसमें खाड़ी देशों ने ईरान को संतुलित करने के उद्देश्य से इराक का समर्थन किया। हालाँकि, यह रणनीति दीर्घकाल में विफल सिद्ध हुई, क्योंकि 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा दिया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

21वीं सदी में US invasion of Iraq एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सद्दाम हुसैन का पतन हुआ और इराक में शक्ति संतुलन बदल गया। इससे ईरान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिला, विशेषकर शिया समूहों के माध्यम से, जिससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो गई। इसके साथ ही, ईरान ने Hezbollah, Hamas तथा हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से अपनी रणनीतिक पहुँच को बढ़ाया, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा किया।

वर्तमान समय में यह ऐतिहासिक प्रक्रिया एक जटिल भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में परिवर्तित हो चुकी है, जहाँ संरचनात्मक असमानता, वैचारिक विभाजन और बाहरी शक्तियों की भूमिका प्रमुख है। Gulf Cooperation Council (GCC) देशों की सीमित जनसंख्या और सैन्य क्षमता के कारण वे United States पर सुरक्षा के लिए निर्भर हैं, जबकि ईरान अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न सामरिक साधनों का उपयोग करता है। इस प्रकार, ईरान–अरब खाड़ी संबंधों का ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि वर्तमान संघर्ष आकस्मिक नहीं, बल्कि दीर्घकालीन संरचनात्मक और वैचारिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जहाँ पूर्ण समाधान की बजाय संघर्ष प्रबंधन ही यथार्थवादी विकल्प प्रतीत होता है।

ईरान–खाड़ी देशों के मध्य संरचनात्मक शक्ति असमानता का विश्लेषण:

ईरान और Gulf Cooperation Council (GCC) देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता को केवल वैचारिक या सामरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि गहरी संरचनात्मक शक्ति असमानता के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। लगभग 8–9 करोड़ जनसंख्या और विशाल भू–क्षेत्र वाला ईरान दीर्घकालिक संघर्षों में रणनीतिक धैर्य क्षमता रखता है, जबकि GCC देशों की सीमित नागरिक आबादी उन्हें मानवबल और सामरिक गहराई में कमजोर बनाती है। भौगोलिक रूप से ईरान का नियंत्रण Strait of Hormuz जैसे चोकपॉइंट पर है, जहाँ से विश्व के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है, जिससे वह बिना प्रत्यक्ष अवरोध के भी ड्रोन, मिसाइल और समुद्री खतरों के जरिए वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत GCC देशों के पास ऐसा भू–राजनीतिक leverage नहीं है। सैन्य स्तर पर, यद्यपि खाड़ी देशों के पास आधुनिक हथियार और उच्च रक्षा व्यय है, उनकी शक्ति "भ्रामक श्रेष्ठता" सिद्ध होती है, क्योंकि वे बाहरी समर्थन पर निर्भर हैं, जबकि ईरान असममित युद्ध (Ballistic missiles, Drones, Proxies) के माध्यम से प्रभावी संतुलन बनाता है, जैसा कि Hezbollah और Houthi movement के जरिए देखा गया। यह असंतुलन GCC को United States पर "External Balancing के लिए निर्भर बनाता है, लेकिन 2019 में सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों के दौरान सीमित अमेरिकी प्रतिक्रिया ने इस सुरक्षा गारंटी की अनिश्चितता को उजागर किया। इसलिए यह प्रतिद्वंद्विता एक "संरचनात्मक संघर्ष" है, जिसमें ईरान की पूर्व–सक्रिय बहुस्तरीय रणनीति और GCC की "प्रतिक्रियात्मक निर्भरता" क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाती है, और इसका समाधान संतुलन स्थापित करने में नहीं बल्कि इस असमानता के प्रभावी प्रबंधन में निहित है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और हिंद–प्रशांत समुद्री परिप्रेक्ष्य में भारत का दृष्टिकोण :

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो फारस की खाड़ी को खाड़ी ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ने वाला विश्व का सबसे संकीर्ण किंतु निर्णायक समुद्री मार्ग है, आज हिंद–प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धुरी बन चुका है। मात्र 33 किलोमीटर की अपनी सबसे संकरी चौड़ाई और 3 किलोमीटर की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

शिपिंग लेन के साथ यह जलडमरूमध्य विश्व के प्रमुख चोकपॉइंट्स में से एक है। प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और विश्व के लगभग 20–25 प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का परिवहन इसी मार्ग से होता है। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, 2024–25 में भी यह आंकड़ा लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन बना रहा। यह मार्ग केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि उर्वरकों, अनाज, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वैश्विक व्यापार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भर है। देश का 60–65 प्रतिशत कच्चा तेल और LNG का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए, इस जलडमरूमध्य की सुरक्षा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और समग्र हिंद–प्रशांत रणनीति के लिए केंद्रीय महत्व रखती है। यह मात्र एक आर्थिक गलियारा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री महत्त्वाकांक्षा और उसकी समुद्री नीति की रणनीतिक धुरी भी है।

हाल के वर्षों में, विशेषकर जून 2025 में ईरानी संसद द्वारा होर्मुज को बंद करने की मंजूरी और अमेरिका द्वारा ईरान के तीन सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को अभूतपूर्व स्तर पर पहुँचा दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने प्रत्यक्ष बंदी की बजाय ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज गति वाली नौकाएँ और समुद्री खदानें लगाकर इस मार्ग को प्रभावी रूप से बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप जहाजों की आवाजाही में 95 प्रतिशत तक की कमी आई, बीमा लागत आसमान छू गई और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के निकट पहुँच गईं। एशिया, विशेषकर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस संकट ने सिद्ध कर दिया कि होर्मुज का कोई प्रभावी समुद्री विकल्प नहीं है और सीमित पाइपलाइन क्षमता भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकती।

भारत के दृष्टिकोण से यह संकट अत्यंत चिंताजनक है। यदि होर्मुज बाधित होता है, तो तेल की कीमतों में तेज वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, बल्कि चालू खाता घाटा, रुपए की कमजोरी, परिवहन लागत और विनिर्माण क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालेगी। समयबद्ध उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उर्वरक और अनाज की आपूर्ति में व्यवधान से कृषि लागत बढ़ेगी। खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत लगभग आठ लाख भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा भी गंभीर संकट में आ सकती है। इस प्रकार, होर्मुज संकट भारत के लिए केवल ऊर्जा आपूर्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है।

भारत की समुद्री रणनीति इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र में है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति निरंतर बढ़ाई है और ओमान के दक्म बंदुरगाह के साथ रक्षा सहयोग तथा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच का वैकल्पिक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है, जो होर्मुज संकट की स्थिति में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

दीर्घकालिक दृष्टि से भारत को तीन स्तरों पर कार्य करना होगा। प्रथम, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण — रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल तथा LNG आयात बढ़ाना। द्वितीय, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना और QUAD जैसे बहुपक्षीय गठबंधनों के साथ समन्वय बढ़ाना। तृतीय, बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर मुक्त नौवहन, समुद्री सुरक्षा और संप्रभुता के सिद्धांतों का सक्रिय समर्थन करना।

होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है; यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी और भारत के सामरिक हितों की जीवनरेखा है। जब यह धमनी काँपती है, तब भारत जैसे उभरते महाशक्ति को दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता, समुद्री शक्ति और बहुआयामी कूटनीति के संतुलित मिश्रण के माध्यम से ही भारत इस संकट को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और हिंद–प्रशांत में अपनी बढ़ती भूमिका को मजबूत करने का अवसर बना सकता है। होर्मुज की स्थिरता सुनिश्चित करना भारत और समूचे हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए अब एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है।

Map:1. Strait of Hormuz

Source: - https://www.ofimagazine.com/news/iran— considers— closing— strait— of— hormuz— after— israeli— strikes— lawmaker— says

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

Table: 1 भारत के ऊर्जा स्रोत :

क्रम संख्या	ऊर्जा स्रोत	प्रकार	अनुमानित हिस्सेदारी (%)	मुख्य विशेषताएँ
1	कोयला	गैर–नवीकरणीय	~55–60%	बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत, सबसे अधिक उपयोग
2	तेल (पेट्रोलियम)	गैर–नवीकरणीय	~25–30%	परिवहन और उद्योग में उपयोग, आयात पर निर्भर
3	प्राकृतिक गैस	गैर–नवीकरणीय	~6–7%	अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन, उर्वरक व बिजली में उपयोग
4	जलविद्युत	नवीकरणीय	~10–12%	स्वच्छ ऊर्जा, भौगोलिक सीमाएँ
5	सौर ऊर्जा	नवीकरणीय	~6–8%	तेजी से बढ़ता क्षेत्र, सरकारी प्रोत्साहन
6	पवन ऊर्जा	नवीकरणीय	~4–5%	दक्षिण और पश्चिम भारत में अधिक
7	परमाणु ऊर्जा	गैर–नवीकरणीय	~2–3%	कम उत्सर्जन, लेकिन सीमित योगदान
8	बायोमास	नवीकरणीय	~2–3%	ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग

Source: International Energy Agency (IEA). (2024). *India – Electricity mix and energy profile*. Retrieved from India energy profile (IEA)

ईरान संघर्ष में भारत की मध्यस्थता: कूटनीतिक क्षमता का यथार्थवादी विश्लेषण :

हाल ही में प्रकाशित एक लेख में Happymon Jacob ने Hindustan Times में अपने कॉलम के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जो लोग भारत से मध्यस्थता की मांग कर रहे हैं, वे वास्तव में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह चाहते हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर सक्रिय दिखाई दे, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसका पड़ोसी ऐसा कर रहा है। उनके अनुसार यह वास्तविक राज्यकला नहीं, बल्कि मात्र अहंकार है। वर्तमान में भारत में इस बात पर तीखी बहस चल रही है कि क्या उसे अमेरिका–ईरान संघर्ष में मध्यस्थता करनी चाहिए। इसके समर्थकों का मानना है कि तेहरान, वॉशिंगटन और खाड़ी देशों के साथ भारत के विशेष संबंध तथा उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा उसे एक स्वाभाविक मध्यस्थ बनाती है। साथ ही, कुछ विद्वान कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 के बीच के दौरान नेहरूवादी कूटनीति का

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

उदाहरण देते हुए यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भारत पूर्व में भी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो पुनः ऐसी भूमिका निभा सकता है।

हालाँकि, जैकब इस तर्क को भ्रामक मानते हैं। उनके अनुसार प्रभावी मध्यस्थता के लिए केवल अच्छे कूटनीतिक संबंध पर्याप्त नहीं होते, बल्कि मध्यस्थ के पास ठोस रणनीतिक हित और प्रभाव होना अनिवार्य है, जिससे वह संबंधित पक्षों पर दबाव डालकर समझौता सुनिश्चित कर सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में United States और Iran के बीच किसी भी संघर्ष में वास्तविक प्रभाव China और Russia जैसी बड़ी शक्तियों के पास है।

भारत के पास न तो पर्याप्त leverage है और न ही वह किसी पक्ष को समझौते के लिए बाध्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत के दोनों पक्षों के साथ महत्वपूर्ण संबंध होने के कारण असफल मध्यस्थता की स्थिति में उसे कूटनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः बिना पर्याप्त शक्ति और रणनीतिक क्षमता के मध्यस्थता का प्रयास वास्तविक कूटनीति नहीं, बल्कि केवल एक दिखावटी कदम होगा।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति विविधीकरण: 2026 के पश्चिम एशिया संकट के बीच एक सक्रिय और बहुआयामी रणनीति

2026 के पश्चिम एशिया संकट, विशेष रूप से ईरान–इजरायल–संयुक्त राज्य संघर्ष और Strait of Hormuz में उत्पन्न तनाव के बीच, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक दूरदर्शी और सक्रिय रणनीति अपनाई है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर संचालित हो रही हैं तथा पर्याप्त कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाए रखा गया है।

वर्तमान में भारत प्रतिदिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर तथा पाँचवाँ सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक है। ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, UAE से "Jag Laadki" टैंकर द्वारा लगभग 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया जा रहा है, जबकि Mundra और Kandla बंदरगाहों पर 90,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले बड़े LPG कार्गो मंगाए जा रहे हैं। साथ ही, घरेलू LPG उत्पादन में 25–36% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे आपूर्ति स्थिरता में मदद मिल रही है।

रणनीतिक रूप से भारत ने तेल आयात स्रोतों का व्यापक विविधीकरण किया है। वर्तमान में कच्चा तेल लगभग 40 विभिन्न देशों से आयात किया जा रहा है और कुल आयात का करीब 70% वैकल्पिक समुद्री मार्गों से लाया जा रहा है, जिससे Strait of Hormuz पर निर्भरता काफी हद तक कम हुई है। फिर भी, लगभग 40% कच्चा तेल और 50% से अधिक LNG अभी भी इस संवेदनशील मार्ग से आता है, जो एक प्रमुख संरचनात्मक जोखिम बना हुआ है।

सरकार ने इस जोखिम को कम करने के लिए 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, गैस नियंत्रण आदेश जारी किए हैं तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ₹300 अरब की LPG सब्सिडी का प्रावधान किया है। समुद्री सुरक्षा और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

Map: 1.2

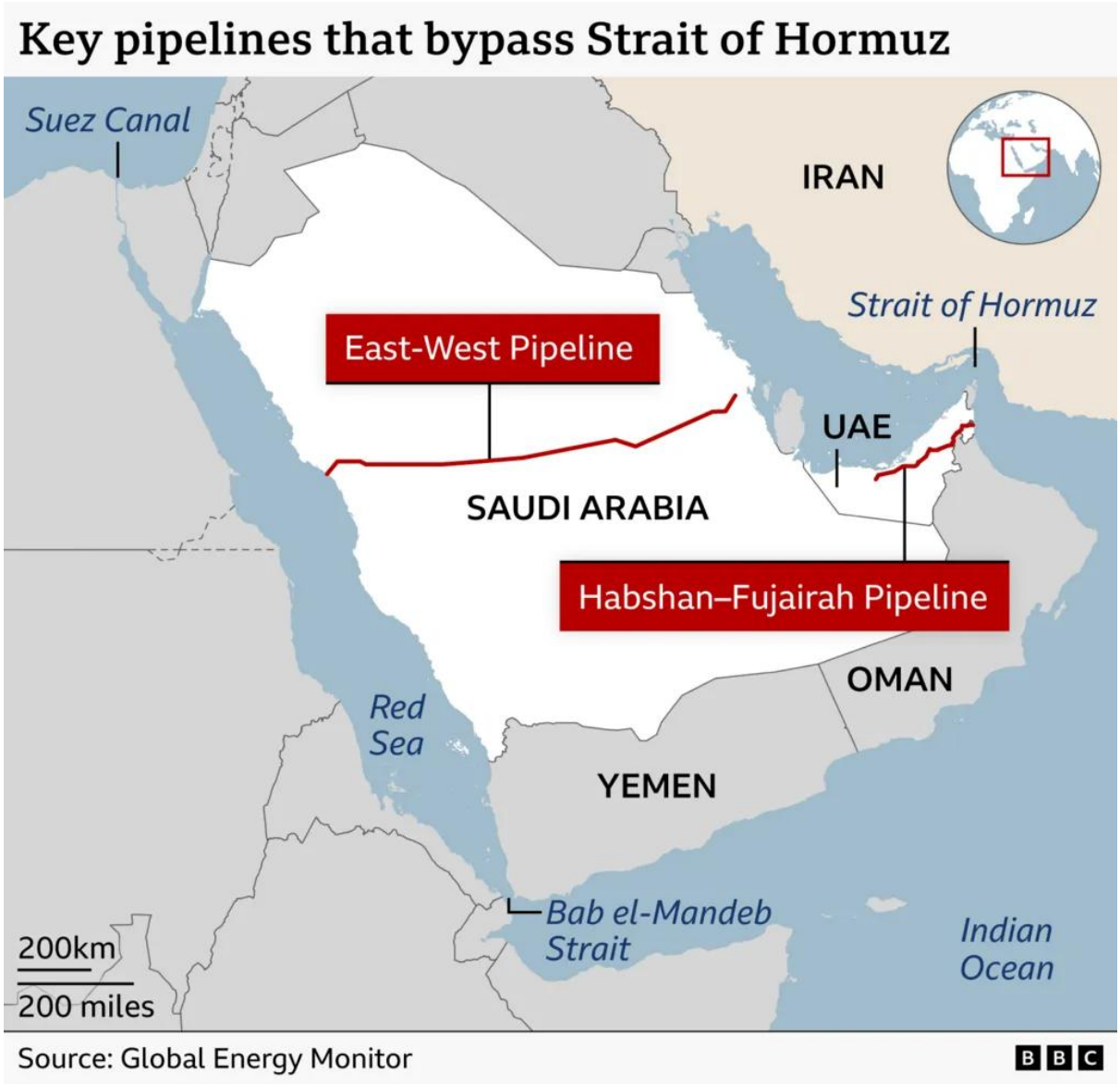

Source :

https://www.bbc.com/news/articles/c78n6p09pzno

वैश्विक तेल कीमतों में तेज वृद्धि (जैसे +113 प्रति बैरल तक) के संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कमी या Shortage से बचाने के लिए कड़े और डेटा–आधारित कदम उठाए हैं। सभी तेल और गैस कंपनियों को अपने निर्यात, आयात तथा भंडार का पूरा डेटा—चाहे वह व्यावसायिक रूप से संवेदनशील क्यों न हो—अनिवार्य रूप से Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया है। इस डेटा के आधार पर सरकार समय पर लक्षित हस्तक्षेप कर रही है, जैसे निर्यात पर अस्थायी नियंत्रण लगाना या घरेलू जरूरतों के अनुरूप आपूर्ति को समायोजित करना। भारत अपनी 90% से अधिक तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है, इसलिए वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। Strait of Hormuz में संकट के कारण LPG आपूर्ति

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

लगभग बाधित हो गई थी, जिससे दशकों का सबसे बड़ा रसोई गैस संकट पैदा हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने तथा उद्योग क्षेत्र को आपूर्ति कम करने का निर्देश दिया, ताकि देश के 33 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें बिना किसी व्यवधान के पूरी की जा सकें। साथ ही जनता से पैनिक बाइंग न करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को अपनाने की अपील की गई है।

ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत ने लगभग 60 दिनों की कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। देश के कुल भंडारण क्षमता 74 दिनों की है, जिसमें से 60 दिन की मांग पूरी करने लायक स्टॉक उपलब्ध है। संकट के कारण मध्य–पूर्व से होने वाले 40% से अधिक आयात प्रभावित हुए थे, लेकिन भारत ने इस कमी को पूरा करने के लिए पश्चिमी गोलार्ध से अधिक तेल खरीदना शुरू कर दिया है। साथ ही, अमेरिकी छूट (sanctions waiver) का लाभ उठाते हुए रूसी तेल के आयात में भी वृद्धि की गई है। परिणामस्वरूप, अब भारत को अपने 41 से अधिक वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में बेहतर आपूर्ति प्राप्त हो रही है, जिससे Hormuz मार्ग पर निर्भरता आंशिक रूप से कम हुई है। LPG संकट को विशेष रूप से संबोधित करते हुए सरकार ने घरेलू उत्पादन को 40% बढ़ाकर लगभग 50,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है (जबकि दैनिक आवश्यकता करीब 80,000 मीट्रिक टन है)। इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त LPG का आयात सुनिश्चित किया गया है, जो लगभग एक महीने की आपूर्ति के बराबर है।

कुल मिलाकर, भारत ने आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण, घरेलू उत्पादन वृद्धि, रणनीतिक भंडारण प्रबंधन, डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रिया और वैश्विक स्रोतों के कुशल उपयोग के माध्यम से एक मजबूत "strategic buffer" तैयार किया है। यह बहुआयामी रणनीति अल्पकालिक संकटों के प्रभाव को नियंत्रित करने में सफल रही है और ऊर्जा सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया है। हालांकि, Strait of Hormuz पर अभी भी बनी हुई निर्भरता एक गंभीर संरचनात्मक जोखिम बनी हुई है, जिसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है। भारत की यह सक्रिय और दूरदर्शी ऊर्जा नीति न केवल वर्तमान संकट को सफलतापूर्वक प्रबंधित कर रही है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी देश को बेहतर ढंग से तैयार कर रही है।

भारत में Strait of Hormuz" पर निर्भरता कम करने के उपाय: एक बहुआयामी रणनीति

2026 के पश्चिम एशिया संकट के दौरान Strait of Hormuz में उत्पन्न तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दी, क्योंकि देश का लगभग 40% कच्चा तेल और 50% से अधिक LNG अभी भी इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजरता है। हालांकि, भारत ने इस निर्भरता को व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए कई ठोस और दूरदर्शी उपाय अपनाए हैं, जिससे कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 70% अब वैकल्पिक समुद्री मार्गों से लाया जा रहा है। यह प्रगति पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय है, जब यह आंकड़ा करीब 55% था। सरकार की सक्रिय रणनीति आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण, वैकल्पिक मार्गों के उपयोग, घरेलू उत्पादन वृद्धि, रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो अल्पकालिक जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

सबसे प्रमुख उपाय ''आयात स्रोतों का व्यापक विविधीकरण'' है। भारत वर्तमान में कच्चा तेल लगभग 40 विभिन्न देशों से आयात करता है, जिसमें रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है (कई बार 30–35% हिस्सा)। अमेरिकी प्रतिबंध छूट (Sanctions waiver) का लाभ उठाते हुए रूसी तेल के आयात में वृद्धि की गई है, जो Hormuz मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। साथ ही, पश्चिमी गोलार्ध (Western hemisphere) से आयात बढ़ाया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, गुयाना, कोलंबिया और वेनेजुएला शामिल हैं। अफ्रीका से नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों से भी महत्वपूर्ण मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है, जो अटलांटिक मार्ग से आता है। इन स्रोतों से आयात लंबे समय (25–45 दिन) लेता है, लेकिन Hormuz से जुड़े जोखिम को पूरी तरह टालता है। Gulf क्षेत्र से भी कुछ आपूर्ति को बायपास मार्गों से सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसे सऊदी अरब का East–West पाइपलाइन (Yanbu पोर्ट तक) और UAE का Fujairah पाइपलाइन (Gulf of Oman तक), जिनकी संयुक्त क्षमता करीब 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन है।

दूसरा महत्वपूर्ण उपाय ''वैकल्पिक समुद्री मार्गों'' का उपयोग है। रूसी तेल Suez Canal या Cape of Good Hope के रास्ते भारतीय महासागर पहुंचता है, जबकि अमेरिका और लैटिन अमेरिका से आने वाले कार्गो भी Hormuz से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इन मार्गों पर निर्भरता बढ़ाने से Hormuz पर कुल निर्भरता काफी कम हुई है। LPG और LNG के मामले में भी विविधीकरण तेज किया गया है—अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी उत्पादकों से अतिरिक्त Cargoes मंगाए जा रहे हैं। सरकार ने LNG स्रोतों को Gulf (कतर, UAE) से हटाकर नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा है, ताकि Hormuz से जुड़े 50%+ LNG आयात का जोखिम कम हो।

तीसरा स्तंभ ''घरेलू उत्पादन और क्षमता वृद्धि'' है। LPG घरेलू उत्पादन को 25–40% तक बढ़ाया गया है (लगभग 50,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन), जबकि रिफाइनरियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकतम क्षमता पर चलें और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दें। कच्चे तेल के लिए भी घरेलू अन्वेषण को तेज किया जा रहा है, हालांकि आयात पर निर्भरता अभी भी 85–90% है।

चौथा उपाय ''रणनीतिक भंडारण क्षमता'' का विस्तार और प्रबंधन है। भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें से लगभग 60 दिन की मांग पूरी करने लायक स्टॉक उपलब्ध है। Strategic Petroleum Reserves (SPR) की वर्तमान क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है (जिसमें से 64% भरा हुआ), जो करीब 9–10 दिनों की आपूर्ति प्रदान करती है। सरकार ने Phase–II विस्तार के तहत अतिरिक्त क्षमता (6.5 मिलियन टन तक) विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि कुल SPR 90 दिनों की कवरेज की ओर बढ़े। रिफाइनरियों के इन्वेंटरी और ट्रांजिट स्टॉक भी इस बफर को मजबूत करते हैं।

अंत में, दीर्घकालिक समाधान के रूप में ''नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और विकल्प'' को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक कुकिंग समाधान, सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ स्रोतों को प्रोत्साहन देकर तेल–गैस आयात पर निर्भरता को धीरे–धीरे कम किया जा रहा है। सरकार ने 24×7 नियंत्रण कक्ष, डेटा साझाकरण अनिवार्यता (PPAC के माध्यम से) और Natural Gas Control Order जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों से भी आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत किया है।

इन उपायों का संयुक्त प्रभाव यह है कि भारत अब किसी एक चोकपॉइंट या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर नहीं रह गया है। हालांकि, Hormuz पर बची हुई 30% निर्भरता अभी भी एक संरचनात्मक जोखिम है, जिसे पूरी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

तरह समाप्त करने के लिए और अधिक निवेश, डिप्लोमेसी और घरेलू क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, भारत की यह सक्रिय रणनीति न केवल वर्तमान संकट को प्रबंधित कर रही है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत "strategic buffer" भी तैयार कर रही है, जो ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रही है।

निष्कर्ष– Iran–पश्चिम एशिया संकट और Strait of Hormuz में उत्पन्न अस्थिरता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री शक्ति और भू–राजनीतिक संतुलन एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस परिवर्तित परिदृश्य में India केवल एक संवेदनशील उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरती हुई जिम्मेदार और रणनीतिक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है।

यद्यपि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है और Hormuz जैसे चोकपॉइंट पर निर्भरता एक संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है, फिर भी भारत ने जिस दूरदर्शिता और सक्रियता के साथ इस संकट का सामना किया है, वह उसकी बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। आपूर्ति स्रोतों का व्यापक विविधीकरण, 40 से अधिक देशों से आयात, वैकल्पिक समुद्री मार्गों का उपयोग, 60 दिनों से अधिक का रणनीतिक भंडारण, और घरेलू उत्पादन में वृद्धि—ये सभी कदम यह संकेत देते हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि एक "पूर्व–सक्रिय" और आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में उभर रहा है।

साथ ही, भारत की समुद्री रणनीति—हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, मित्र देशों के साथ सहयोग, और वैश्विक मंचों पर मुक्त नौवहन (freedom of navigation) के सिद्धांतों का समर्थन—यह दर्शाती है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को व्यापक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ जोड़कर देख रहा है। यह दृष्टिकोण न केवल भारत के हितों की रक्षा करता है, बल्कि पूरे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन को भी सुदृढ़ करता है।

आर्थिक दृष्टि से भी, यद्यपि तेल कीमतों में उतार–चढ़ाव भारत के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं, फिर भी उसकी मजबूत नीतिगत क्षमता, बाजार प्रबंधन और संस्थागत ढांचा उसे इन झटकों को सहने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में उठाए गए कदम भविष्य में उसकी आयात निर्भरता को क्रमशः कम करेंगे और उसे अधिक आत्मनिर्भर बनाएंगे। कूटनीतिक स्तर पर, भारत ने संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाते हुए सभी प्रमुख शक्तियों—अमेरिका, रूस, खाड़ी देशों और अन्य वैश्विक भागीदारों—के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखा है। यह "रणनीतिक स्वायत्तता" भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे किसी एक ध्रुव पर निर्भर होने से बचाती है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन प्रदान करती है।

अतः, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान संकट भारत के लिए केवल चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर भी है—अपने ऊर्जा ढांचे को अधिक सुरक्षित, विविध और टिकाऊ बनाने काय अपनी समुद्री शक्ति को सुदृढ़ करने काय और वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार, स्थिरता–प्रदाता के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने का। यदि भारत इसी प्रकार संतुलित कूटनीति, बहुस्तरीय रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है, तो वह न केवल इस संकट से सफलतापूर्वक उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा और भू–राजनीतिक व्यवस्था में एक निर्णायक और सकारात्मक शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- Jacob, H. (2026, March 30). *Why India can't be a mediator in Iran war*. Hindustan Times.
- International Energy Agency (IEA). (2024). *India – Electricity mix and energy profile*. Retrieved from India energy profile (IEA)
- Ember. (2024). *India electricity mix 2024*. Retrieved from India energy mix data (Ember)
- Economic Times. (2026). *Iran–Israel–US conflict: India aims for stronger fuel shield*. Retrieved from: https://m.economictimes.com/industry/energy/oil-gas/iran-israel-us-conflict-impact-on-india-oil-supply-new-delhi-aims-for-stronger-fuel-shield-as-hormuz-crisis-tests-indias-energy-security/articleshow/129441574.cms (The Economic Times)
- India Briefing. (2026). *India's oil supply diversification strategy amid Hormuz crisis*. Retrieved from: https://www.india-briefing.com/news/indias-oil-supply-hormuz-diversification-strategy-43381.html/ (India Briefing)
- Economic Times. (2026). *India orders oil firms to share data amid West Asia crisis*. Retrieved from: https://m.economictimes.com/industry/energy/oil-gas/us-israel-iran-war-india-orders-oil-firms-to-share-data-as-west-asia-war-jolts-supplies/articleshow/129675159.cms (The Economic Times)
- Reuters. (2026). *India secures 60 days of oil supply amid Hormuz disruption*. Retrieved from: https://www.reuters.com/business/energy/india-secures-60-days-oil-supply-amid-hormuz-disruption-2026-03-26/ (Reuters)

1.